











## बांग्लादेश में अनिश्चितता

## युनूस सरकार पर दबाव

बांगलादेश की सेना ने बढ़ी अराजकता एवं संबंधों में गिरावट के समय यह कह कर यूनुस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह भारत के साथ मजबूत संबंध चाहती है। बांगलादेश वर्तमान समय में राजनीतिक अनिश्चितता तथा अशांति का शिकार है क्योंकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार तथा देश में शक्तिशाली सैनिक अवस्थापना के बीच भी विरोधाभास पैदा हो गए हैं। हाल ही में ढाका इंटरनेशनल मैराठन, 2025 में सेना प्रमुख जनरल वकारूज्जमा ने सिविलियन सरकार के प्रति सेना के दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन का संकेत दिया। उन्होंने शांति, स्थायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत के साथ सहयोग पर जोर दिया। इससे सेना की कतारों में यूनुस प्रशासन की नीतियों व शासन के दृष्टिकोण के प्रति बढ़ते विरोध का संकेत मिलता है। बांगलादेश की सेना ने ऐतिहासिक रूप से आंतरिक स्थायित्व बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अक्सर राजनीतिक संकट कावू के बाहर जाने पर उसने हस्तक्षेप किया है। यूनुस सरकार के नेतृत्व में राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण लगता है कि सेना स्वर्य को प्रशासन से दूर रख रही है जो देश के सत्ता समीकरणों में बदलाव का संकेत है। यूनुस सरकार से सेना के असंतोष के अनेक कारण हो सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि सेना को यूनुस सरकार के नेतृत्व में खराब होती आर्थिक श्रितियों तथा बढ़ते सामाजिक तनाव की चिन्ता है। लगातार जारी राजनीतिक अशांति के कारण विदेशी



खास चिन्ता का विषय है। बांगलादेश का सैनिक नेतृत्व प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को महत्व देता है। भारत के बारे में जनरल वकार की टिप्पणी से ऐसे व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोण के प्रति सेना की इच्छा प्रकट होती है जिसमें लोकरंजक लफाजी के आधार पर बने वैचारिक दृष्टिकोणों के बाजाय स्थायित्व तथा परस्पर लाभ को प्राथमिकता मिलती हो। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमा के बयान में जोर दिया गया है कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग में प्रमुख साझेदार है। इस बयान से बांगलादेश की विदेश नीति में रणनीतिक समीक्षा की स्थिति रेखांकित होती है। उन्होंने कहा कि बांगलादेश ‘अनेक मामलों में भारत पर निर्भर है’ तथा दोनों देशों को एक दूसरे के रणनीतिक हितों का सम्मान करना चाहिए। जनरल का यह बयान नई दिल्ली के साथ निकट संबंधों की पैरवी करता लगता है। भारत और बांगलादेश के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं जिनमें व्यापार, ऊर्जा सहयोग तथा ढांचागत परियोजनायें शामिल हैं। भारत के साथ स्थाई संबंधों से निरंतर आर्थिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होती है। आतंकवाद-विरोधी प्रयासों में सहयोग तथा सीमा प्रबंधन शांति और स्थित्यित्व बनाए रखने के लिए जरूरी है। बांगलादेश का सैनिक नेतृत्व शायद भारत के साथ मजबूत संबंधों के पक्ष में है क्योंकि इसका अर्थ संतुलित विदेश नीति अपनाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ढाका कि सी क्षेत्रीय शक्ति पर अत्यधिक निर्भर न होने पाए। वर्तमान समय में बांगलादेश में सिविल सरकार और सेना के बीच बढ़ती विसंगतियों का संकेत मिलता है, जबकि अने वाले महीनों में देश की दिशा निर्धारित करने में सिविलियन नेतृत्व तथा सैनिक अवस्थापना के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

‘विश्व रेडियो दिवस’ मनाते समय ‘मन की बात’ हमें याद दिलाती है कि संप्रेषण के आधार वही बने हुए हैं। इनमें लोगों को जोड़ना, प्रेरित करना तथा उनको एकसाथ लाना शामिल है।



दियो केवल एक माध्यम न होकर  
एक ऐसी जीवनरेखा है जो  
सीमाओं को पार कर लोगों को एकसाथ  
जोड़ती तथा उनके स्वरों को विस्तार देती  
है। 'विश्व रेडियो दिवस' मनाते समय  
दुनिया इस स्थाई मंच की शक्ति का उत्सव  
मना रही है। भारत इस उल्लेखनीय संचार  
क्रांति में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री  
नरेन्द्र मोदी के मासिक प्रसारण 'मन की  
बात' की हाल ही में 118वीं कड़ी प्रसारित  
हुई। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल युग  
में भी रेडियो एक पुनर्जीवन का अनुभव  
कर रहा है और यह सुशासन, अभिप्रणाली  
तथा भावनात्मक राजनय का सर्वाधिक  
प्रभावी उपकरण सिद्ध हो रहा है।



सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय उपलब्धियों की भी चर्चा करती है। इस दृष्टिकोण से 'मन की बात' की 118वें कड़ी भी कुछ अलग नहीं थी। इसमें उन विमर्शों को शामिल किया गया था जो राष्ट्र-निर्माण की भावना पैदा करते हैं, पर्यावरण के प्रति चेतना का विस्तार करते हैं तथा सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पर जोर देते हैं। अपने राष्ट्रीय आकर्षण के साथ ही 'मन की बात' भारत की भावनात्मक राजनय का महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। दुनिया भर में रहने वाले अनिवासी भारतीय बड़ी जिज्ञासा से इस कार्यक्रम को सुनते हैं और इस प्रकार वे अपनी जन्मभूमि से एक प्रकार से जुड़ाव का अनुभव करते हैं। इसका प्रसारण राष्ट्रीय सीमाओं के पार जाता है और अक्सर इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद भी होता है।

'मन की बात' का प्रसारण दक्षिण एशिया की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में होता है जिससे पड़ोसी देशों के साथ भारत के राजनयिक व सांस्कृतिक संबंध मजबूत होते हैं। विश्व में प्रमुख रूप के रूप में उभरे रहे भारत ने अपनी भावनात्मक प्रसारण का विस्तार नहीं दे सका रखा

राष्ट्र की ऐसी छवि उभरती और मजबूत होती है जिसमें संवाद, साझा विरासत सहयोग को महत्व दिया जाता है। दक्षिण-एशिया दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक व भाषण संबंधों से बंधा है। इन स्थितियों में विभिन्न भाषाओं में प्रसारित 'मन की बात' एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस अत्यधिक लोकप्रिय कार्यक्रम के विषयों में आत्मनिर्भरत समुदाय-संचालित पहलें, पर्यावरण व टिकाऊपन तथा युवाओं का सशक्तीकरण शामिल हैं। ये विषय न केवल भारत ही लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये भारत द्वारा पड़ोसी देशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं।

ऐसे समय में जब दक्षिण एशिया अक्सर समन्वय के प्रयासों को अनेक राजनीतिक बाधाओं का सामना करता है, तब उसकी विरासती विविधता पड़ता है, सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान के माध्यम के रूप में रेडियो का पुनर्जीवन असाधारण संभावनाओं से भरा लगता है। 'मन की बात' के माध्यम से भारत की रेडियो राजनय में भी असाधारण संभावना सामने आती है।

इससे साझा विकासोन्मुख विमान विकसित हो सकते हैं तथा क्षेत्रीय जनसंख्या के बीच साझा महत्वाकांक्षाओं का विकास भी हो सकता है।

‘मन की बात’ की 118वीं कड़ी यह प्रदर्शित किया है कि रेडियो का प्रयोग सहभागी माध्यम के रूप में कैसे किया जा सकता है। नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद में अक्सर श्रोताओं द्वारा लिखे पत्रों तथा उनके संदेशों व महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। जन-केन्द्रिय प्रशासन पर इस प्रकार जोर दे कर ‘मन की बात’ जनता के विभिन्न समूहों के बीच संवाद का विशिष्ट ‘स्पेस’ तैयार करता है। यह उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों एकदम अलग है जो अक्सर विभाजित तथा शोर व प्रतिव्यवनि से भरे होते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से रेडियो एक ऐसा एकीकरण शक्ति के रूप में सामने आया जो जनता को अबाध रूप से तथा गहरे से आपस में जोड़ता है।

‘मन की बात’ में तमिलनाडु ने मछुआराओं से लेकर पंजाब के किसानों तक मेघालय के छात्रों से लेकर गुजरात तक उद्यमियों की बातें शामिल होती हैं। इसका उत्तर वर्षान्त शर्षार्थी और नियन्त्र

हर भारतीय से से बात करता है। अपनी कहानी कहने की शक्ति के माध्यम से यह कार्यक्रम अनाम नायकों, छोटे बिजनेसों तथा संस्कृति के संरक्षकों के स्वर सापेने लाता है। रेडियो हमेशा से प्रभावशाली माध्यम रहा है, पर 'मन की बात' ने परंपरागत प्रसारण को आधुनिक डिजिटल समन्वय से जोड़ कर एक कदम आगे बढ़ाया है। इस कार्यक्रम को एकसाथ अनेक प्लेटफर्मों पर जारी किया जाता है जिनमें समुदायिक रेडियो स्टेशन, आल इंडिया रेडियो-एआईआर, पाइकास्ट और सोशल मीडिया चैनल शामिल हैं।

इस हाइब्रिड मालद ने सुनिश्चित किया है कि संदेश हर प्रकार की जनसंख्या तक पहुँचे जिसमें ट्रांजिस्टर रेडियो का प्रयोग करने वाले ग्रामीण किसान से लेकर स्मार्टफोन एप से जुड़ने वाले पेशेवर शहरी लोग तक शामिल हैं। 'विश्व रेडियो दिवस' पर जब दुनिया भर में रेडियो के पुनर्जीवन और प्रभाव पर चर्चा हो रही है, ऐसे में 'मन की बात' एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आता है कि कैसे इस माध्यम का प्रयोग राष्ट्र-निर्माण व राजनय में किया जा सकता है। दुनिया भर के देश भारत द्वारा एक उपकरण के रूप में रेडियो के प्रयोग से सबक सीख सकते हैं जो रचनात्मक संवाद, नेतृत्व से संवाद तथा वैश्विक संपर्क का माध्यम बन गया है।

ऐसे युग में जब धूलीकरण व्यापक हो गया है, रेडियो की क्षमता सामूहिक चेतना विकसित करने के रूप में सामने आई है। यह विशाल व विविधतापूर्ण भारत के लिए ज्यादा मूल्यवान है। 'मन की बात' में उन स्वरों को एकीकृत किया गया है जो लोगों की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर की शक्ति, शब्दों के जादू तथा मौखिक कहानी कहने जैसे गहन तत्वों के कारण यह कार्यक्रम एक राजनीतिक पहल से आगे बढ़ कर एक सांस्कृतिक अवधारणा बन गया है। दुनिया इस समय परंपरागत संप्रेषण प्लेटफर्मों को पुनर्जीवित करने के तरीके खोज रही है।

ऐसे में भारत के उदाहरण से स्पष्ट है कि रेडियो न केवल जीवंत बना हुआ है, बल्कि यह डिजिटल युग में भी फ़ल-फूल रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मासिक 'मन की बात' कार्यक्रम इस पुनर्जीवन का नेतृत्व करते हुए यह सिद्ध कर रहा है कि 'डिजिटल शोर' के युग में भी मानवीय सत्त्वों में एक नया ज्ञान वाला ऐनियर बनते

# एक आरथा, एक जगत

स्थापित करना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने लोगों को एक साझा मंच पर लाने और

प्रत्येक धर्म की बेहतर समझ और स्वीकृति बनाने के तरीके और साधन खोजने का बार-बार प्रयास किया है। लेकिन उनके कठिन प्रयासों के बावजूद, बहुत कुछ नहीं बदला है। इसलिए, वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विभिन्न धर्म और आस्थाएं कभी एकजुट हो सकती हैं? यदि हाँ, तो कैसे?

A silhouette of a person standing with arms raised, looking up at a flock of birds flying in a clear sky.

दुनिया भर में संगठित समूहों को धर्म के नाम पर आतंक फैलाने और दुनिया से बुराई को दूर करने के नाम पर जातीय सफाया करने की कसम खाते हुए देखना बहुत भयावह है। अगर हम

अविश्वास और शत्रुता को बढ़ावा दि है। यह जानना बहुत ज़स्ती है कि, अप स्थापना के समय, हर धर्म में पवित्र सच्चाई और एकता की शक्ति थी। धीरे धीरे, दररों, गुटबाजी, उथल-पुथल, भ्र छल और आध्यात्मिक महत्व से रि कर्मकांडीय पालन दिखाई देने ल इसलिए, आध्यात्मिक मूल्यों को सश बनाने के बजाय, धर्मों ने हठधर्मिं अनुशासन और बाधाओं को कायम र जो लोगों को कई तरह से अलग-थर

कर देते हैं।  
कई लोग उन्हीं बुराइयों का शिवाय हो जाते हैं जिनके खिलाफ क्षेत्र पुण्डरेश नहीं, जैसे सत्ता, सुख और पैसे व लालसा। प्रत्येक धर्म की बेहतर समस्ति हिंसा और स्वीकृति हो सकती लेकिन जब तक एक या आम विश्वास हो, एकता नहीं हो सकती। तो, सधार्थों को स्वीकार्य एक आम समाधान तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका वह है? सर्वोच्च सर्वशक्तिमान द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान के अनुसार, मानव संसार

गुजरता है, जिसका अर्थ है कि सब कुछ एक परिपूर्ण अवस्था से अपूर्ण, खंडित अवस्था में बदल जाता है। चाहे वह मानव आत्मा हो, प्रकृति हो, धर्म हो या सभ्यता हो, लगभग सब कुछ सतो (शुद्ध), रजो (मिश्रित) और तमो (अशुद्ध) अवस्थाओं से गुजरता है क्योंकि समय चक्र स्वर्ण युग से लौह युग तक है।

तक धूमता ह। आज हम मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं के तमो-प्रधान (सबसे परित) चरण को देख रहे हैं, और धर्म भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया से अद्घृते नहीं हैं। इसलिए, हम सभी धर्मों में निहित आध्यात्मिकता के संदर्भ में ही एकीकृत आस्था की कल्पना कर सकते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, और सच्चा धर्म उस सत्य का प्रतीक है। इसलिए, जब मनुष्य अपने हृदय में उस सत्य को अपना लेंगे, तो एक एकीकृत दुनिया होगी। इसलिए, आइए हम सभी एक एकीकृत आस्था के साथ एकजुट होकर उस नई दुनिया का स्वागत करें जहाँ

## आहे कैसा तारा?

ਮਿਲਾਈ ਮਾਨ

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेवड़ी व मुफ्तखोरी को लेकर विचारोत्तेजक प्रश्न किया गया है कि क्या ऐसा करके हम लोगों को परजीनी नहीं बना रहे हैं ? बेहद विचारणीय है। जब से राजनीतिक दलों द्वारा वोट व सत्ता के लिए मुफ्त की रेवड़ी बांटने का उपक्रम चला है, तब से ही इन अखबारों के पन्नों पर खारीतों को लेकर काफी कुछ लिखा गया है। लेकिन विडेबना की बात है कि राजनीतिक दलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि नई-नई मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं बढ़ती गई। कहीं लाडली बहन के नाम पर तो कहीं लाड़की बहन, न जाने क्या-क्या ? इतनी रेवड़ी की घोषणाएं सुन सुन कर कान पक जाएँ। मगर ये दल-बल वाले नहीं अघोते हैं। मुफ्तखोरी का एक कुपरिणाम यह भी है कि जब इंसान को मुफ्त में मिलने लग जाता है तो निश्चित ही माले मुफ्त दिलएबरहम की कहावत चरितार्थ होने लग जाती है। कोई भी काम करना नहीं चाहता क्योंकि अल्लाह दे खाने को तो क्यों जाएँ। कमाने को ? साथ ही अपवाद स्वरूप लोगों को छोड़ दे तो शत-प्रतिशत यह पैसा शराब/ नशाखोरी में भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह सीख जमीनी स्तर पर कितनी आत्मसात कर पाएँगे ये राजनीतिक दल यह देखने वाली बात है ! मगर यह कोई पहली बार टिप्पणी नहीं की जा रही है। समय-समय पर पहले भी टिप्पणी की गई, लेकिन देशभक्त जनसेवकों के कानों में जूँ तक नहीं रेंगती है।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰਖੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ।

लालय ने कहीं बार राजनीतिक को फटकार लगाई है, किन्तु बार उसने रेवड़ी बांटने के भावों पर भी खुलकर बोला मुफ्त की रेवड़ी के चलन का यों तो स्वर्गीया जयललिता जाता है किन्तु इस चलन को अब चढ़ाया कट्टर ईमानदार बन्द के जरीवाल ने। फिर यह मण्डण धीरे-धीरे सभी गीतिक दलों में फैल गया। दल इस रेवड़ी बांट को देहत के कार्य कहते हैं तो कुछ जनता का अधिकार। किन्तु निस्सदेह घूस देकर मत दिना है। शीर्ष न्यायालय ने कुल ठीक कहा है कि मुफ्त में भी रहा है। एक समय ले मजदूरी के लिए घर - घर जावा काम के लिए पूछते थे, कि आज मजदूरों के घर के चक्र लगाने पड़ते हैं। इससे विकार्यी प्रभावित होते हैं। क्योंकि बजट का एक बहुत बड़ा और रेवड़ी बांटने में खर्च हो जाता है। केन्द्र सरकार का मुफ्त राशन बांटना भी मुफ्त की रेवड़ी ही है। जिसे खरीदने के लिए गर्म मौहल्लों में ठेले वालों को आवश्यक लगाते देखा जा सकता है। इतना बन्द होना चाहिए। इतना अवश्य हो सकता है कि गर्म लोगों को कम मूल्य पर राशन उपलब्ध कराया जाए।

## नियंत्रण की जरूरत

संस्कृति और संस्कारो के बगैर हमारी भौतिक प्रगति कुछ भी माने नहीं रखती है। संस्कारो का अभाव देश और समाज को खोखला करता है। बेशक हम नई सोच रखे लेकिन वह सोच संस्कृति और संस्कारो पर आघात न पहुंचाये इसका भी ध्यान रखे। क्योंकि संस्कार ही जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि पर जो पोर्सा जा रहा है उससे सामाजिक संतुलन के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो रहा है। एक्स से लेकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर ऐसे अश्लील कॉटेंट की भरमार है, जो नई पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इनमें से अधिकांश सामग्री पश्चिमी समाज और संस्कृति की नकल है। देश और समाज में अप संस्कृति की हवा बहाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि डिजिटल कॉटेंट की निगरानी की जाए। इंटरनेट मीडिया पर अपलोड होने वाली सामग्री का का विनियमन किया जाए ताकि भविष्य में मनोरंजन एवं अभिय्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता फैलाने एवं पावन पारिवारिक रिश्तो को शर्मसार करने वाली अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने का दुस्साहस न करे।

- विमलश गणराया, बदनावर, मप्र











